

::आयुक्त (अपील) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan, रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,



Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142

Email: cexappealsrajkot@gmail.com



रजिस्टर्ड डाक ए. डी. दवारा :-

अपील : फाइल संख्या / क Appeal / File No

V2/167/GDM/2017

V2/178/GDM/2017

म्ब आदेश सं / O.I.O. No.

टिजांक /

Date

05/JC/2017-18 06/JC/2017-18 29-05-2017 29-05-2017

अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): रव

KCH-EXCUS-000-APP-072-TO-73-2018-19

आदेश का दिनांक /

12.07.2018

जारी करने की तारीख।

16.07.2018

Date of Order:

Date of issue:

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील), राजकोट द्वारा पारित / Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पद्ध शुरुक/ सेवाकर, राजकोट / जाननगर / गाधीधाय। द्वारा उपरक्षिरित जारी मूल आदेश से सृजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-घ M/s. GPT Steel Industries Ltd., Plot No. 301, GIDC Phase- II, Mitnirohar, Gandhidham Kutch - 370 240.

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नतिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के सप्नक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

- सीमा शुक्क केन्द्रीय उत्पाद शुक्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अधील, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क अधिनियम ,1944 की धारा 358 में अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अलर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/ Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-(A)
- वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं रीवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक न 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/ The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Dellar in all matters relating to classification and valuation. (i)
- उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीम्रा शुल्लः, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं संवाकर अपीलीय ल्यावाधिकरण (सिस्टेट) की परिचम क्षेत्रीय पीठिका, , द्वितीय तल, बहुमाली अवश असाशं अहमदाबाद- २८०१६ को की जानी चाहिए ।/ To the West regional bench of Customs. Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at. 2nd Floor, Bhaumali Shawan Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above (ii)
- अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उध्याद शुल्क (अपील) नियमावर्ती, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निधारित किए गये प्रपत्न EA-3 को बार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनसे से काम एक प्रति के साथ, जार उत्पाद शुल्क की माँग ,ब्याज और तागाया गया जुमीना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुए या 50 लाख रुए तक अथ्या 50 लाख रुए हैं अधिक है तो कम्म १,000/- रुपये अथ्या 10,000/- रुपये अथ्या 10,000/- रुपये का निधारित जमर शुल्क की प्रति प्रत्नजन करें। निधारित शुल्क का भुगतान, सर्वधिन अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्विजनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित के इाफ्ट द्वारा किया जान, धातिए । सर्वधित द्वारत को भुगतान, वैक की उस शाखा में होना चाहिए जहा सर्विधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थान आदेश (स्ट आंडेर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निधारित शुल्क जम करना होगा ।/
 The appeal to the Appellate Tribunal shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a ree of Rs. 1,000/- Rs.10,000/- Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-. (iii)

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अतर्गत सेवाकर नियमवानी, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्न 8.1.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके माथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में अरुग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,व्याज की माँग और अगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथाता 50 लाख रुपए से अधिक है तो कमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संतग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संवधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजस्टा के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक दवारा अपी रेखांकित वैके प्राप्त होगा पर विकास में होना चाहिए जस प्रविधित शुल्क लमा करता होगा।/ (B) 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

The appeal under sub-section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filled in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less. Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs. Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a tee or Rs.500/-

ित्त अधिनियम, 1994 की धारा 8६ की उप-धार(ओ (2) का (24) के अत्यात दर्ज की भयी अपील, खंबाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(24) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सक्याी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्याद शुक्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुक्क द्वारा भारित आदेश की प्रतियाँ सत्यम करें (अनमें भ एक प्रति प्रमाणित होगी वाहिए) और आयुक्त द्वारा जहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क/ सेवाकर, को अपीलीय नवायाधिकरण को आवेश अर्थ के एक निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में सलगन करनी होगी। । (i)

The appeal under sub-section (2) and (2A) of the section 36 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tux Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appends) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal

1

हीमा शुरूक, केन्द्रीय उत्पाद शुरूक एवं सेवाइत अधोरीय प्राधिवयण (सेव्हेट) क प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुरूक अधिनियम 1944 की १११८ ३५एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 में (१११ ८८) के अंतर्गत संयाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीकीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुरूक/सेवा कर मांग के १० प्रतिशत (10%), जब माग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बक्षतें कि इस ११११ के अंतर्गत जमां कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो। (ii)

जिल्हों करणद शुन्स एवं देशकर के अंतरहा जिल्हों के आग पाला अधावत दय साथ दस व वेजदीय उत्पाद शुन्स एवं देशकर के अंतरहा "मांग किए गए शुस्सा" में निम्न शामिल है धारा 11 ही के अंतर्गत एकज संगवेट जमा की ही गई गलत संवि सुनवेट जमा निवासायली के निवास 6 के अंतर्गत देश रकम

- (ii)
- (iii)

- वशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान बिल्लोय (स. 2) अपैनितयम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं हाने।।

For an appeal to be filed before the CESTAT under Dection 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 or the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Solvice Tax, "Duty Demanded" shall include:

- amount determined under Section 11 D;
- (iii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules (iii)

provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act. 2014.

्यात अपराध को प्रसरीक्षण भागेत्रज्ञ । (C)

ारत करकार का पुनरक्षण आवटन : Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरक्षिण व्यक्तिका किम्बरिखित शक्कों से, वैद्धीय अजाद एक्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अवर धविब, क्षारत सरकार, पुनरक्षिण आवेदन ईफाई, किल अजाहका, राजक विधाग, बौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाजा बाहिए। 7

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jervan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- यदि शाल के किसी जुलवान के जामले में, जहां गुलवान किसी आप को किसी कारणाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या किसी एक धंवार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के प्रस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण भ माल के प्रस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में आप के मुक्तरान के मासले में!! In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit nom a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a (i)
- कारत के पाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्धात कर ११ अल के हिम्मिया में प्रयुक्त कच्चे मान पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के खाउले में, जो भारत के पाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र का लियोहर की गरी है। I in case of rebate of duty of excise on goods expected to use country or territory outside India of on excisable material used in (ii)the monufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- যাই চল্লার পুলন বা সুসনার দিও হিলা সকল গৈ বল্লা জীখান যা সূচান বই চাল লিখান দিয়া যায়। है। / in case of goods exported outside India export to Nepat of Bhetan, without payment of duty. (iii)
- कुनिश्चित अस्पाद के उत्पादम शुक्त के भुगतान के लिए आ इष्ट्री केवीट का अधिनियम एवं इसके विभिन्न पावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे अंटेश जो आयुक्त (अर्थता) के द्वारा विस्त अधिनियम (स. 2) 1997 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवां समायाविधि पर या बाद में धारित किए वर है। (iv)
 - Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- उपरोक्त आवेदन की दे परिश्वा एपत्र संख्या EA-3 में, अ की कार्याय उनकार भुरूक (अपीन) नियमापती, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हैं, इस अदोश के संबंधिय के 3 मार के संसर्थत की जानी धारिए । उपरोक्त आदेश के साथ मूल आदेश व अपीन आदेश की दो प्रतियां संसरन की जानी प्राष्टिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुरूक अधिनियम, 1944 की प्रधा 35-65 के तहर निर्धारित शुरूक की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति (v)

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals). Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Augmol. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Society 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- पुर्वाराण आवेदन के साथ बिक्नांतिखित निर्धारित शुरूक कि अदारकों की जानी चाहिए। जहाँ सतरक रकम एक बाख रूपये या उससे कम हो हो राख्ये 2007- का शुक्तांति किया। जाए और यदि संतरन रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो जब्दे 1000 -7 का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accomposited by a fee of 3s. 2007- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 10007- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)
- र्जाद इस आदेश में कई मूल आदेशों का समादेश है तो एउकेह मूल आहाश के लिए शुह्म का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के ऐते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए प्रथातिकारित आधितीय अधारिकारण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appealant Hibunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 larks fee of Rs. 100/- for each. (D)
- प्रथानंद्रभाषित ल्यायालय शुन्क अधिक्रियम, 1975, के अधुसूचीन के अनुसार जूल आदेश एवं स्थणन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का ज्यायालय शुन्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Sts. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)
- होता शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाक्स अपीक्षिण ज्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावती, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामतों को अध्यातित करने वाले शियमों की और भी ध्यानं अकर्मिक्ष किया जाता है। / dirention is also invited to the rules covering meso and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules 1982. (F)
- उच्च अधीलीय पाक्षिकारी को अधील दाखिल करने से अबधित उक्षाक विन्तृत और नदीनतम प्रावधानों के निए, अधीलार्थी विभागीय वैबसाइट (G) www.cbc.gov in ਤੀ ਵੇਧ ਦਸਦੀ है । / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to ਗੱਲਰੂ of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov in

::ORDER IN APPEAL ::

M/s. GPT Steel Industries Ltd Plot No. 301, GIDC, Phase-II, Mithirohar, Gandhidham (Kutch) (hereinafter referred to as "the appellant") filed the appeals against Order-In-Original No. 05/JC/2017-18 dated 28.05.2017 (hereinafter referred to as "the impugned order - 1") and Order-in-Original No. 05/JC/2017-18 dated 28.05.2017 (hereinafter referred to as "the impugned order - 2" and both collectively referred to as "the impugned orders"), passed by the Joint Commissioner, Central Excise and Service Tax, Gandhidham (Kutch) (hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority"). The details of appeals are as under: -

Sr. No.	Appeal No.	Period involved	Date of issue of SCN	Disputed Amount of Credit Rs.
01.	V2/167/GDM /2017	June, 2007 &	26.06.2012	92,47,736/-
		July,2007		(Reversed)
02	V2/178/GDM/2017	17.06.2007 to	06.07.2012	61,27,354/-
		28.02.2008		(Not reversed)

- 2. The brief facts of the case in respect of the impugned order – 1 are that the during audit of records of the appellant by CERA it was noticed that they had cleared 6796.49 MTs of imported goods as such during June, 2007 to July, 2007 by issuing invoice and payment of Basic Excise Duty (CVD), Education Cess and Secondary and Higher Secondary Education Cess, however, did not pay Cenvat Credit taken in respect of Additional Excise Duty (SAD) which was allegedly required as per Rule 3(5) of Cenvat Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as "the Rules"). Show Cause Notice No. V.72/AR-GDM/Commr./142/2012 dated 26.06.2012 was issued to the appellant which was adjudicating by the lower adjudicating authority by confirming demand of Cenvat credit of Rs. 92,47,736/under Rule 14 of the Rules read with Section 11A(4)/proviso to Section 11A(1) of the Central Excise Act, 1944 (hereinafter referred to as "the Act"), ordering recovery of interest under Rule 14 of the Rules read with Section 11AA/11BB of the Act and imposing penalty of Rs. 92,47,736/- under Rule 15 of Rules read with Section 11AC of the Act. 100
- 2.1 The facts of the case in respect of the impugned order 2 are that the during the Audit of records of the appellant it was noticed that they had cleared 109.612 MTs of imported goods, that is, HRPO Coils, as such from 17.06.2007 to 28.02.2008 without reversing Cenvat Credit which was allegedly required as per Rule 3(5) of Cenvat Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as "the Rules"). Show Cause Notice No. V.72/AR-GDM/Commr./153/2012 dated 06.07.2012 was



issued to the appellant which was adjudicating by the lower adjudicating authorit

4

issued to the appellant which was adjudicating by the lower adjudicating authority by confirming demand of Cenvat credit of Rs. 61,27,354/- under Rule 14 of the Rules read with Section 11A(4) / proviso to Section 11A(1) of the Central Excise Act, 1944 (hereinafter referred to as "the Act"), ordering recovery of interest under Rule 14 of the Rules read with Section 11AA / 11BB of the Act and imposing penalty of Rs. 61,27,354/- under Rule 15 of Rules read with Section 11AC of the Act.

- Impugned Order 1 : Aggrieved with the impugned order, the appellant preferred appeal, *inter alia*, contending in respect of the impugned order 1 that demand of Cenvat credit (in respect of special additional duty) for the period June, 2007 and July, 2007 is time barred as they have were filing periodical returns regularly; that the appellant was under bonafide belief that they were required reverse credit taken in respect of additional duty of customs, education cess and secondary and higher secondary education cess at the time removal of goods as such and not required to reverse credit of special additional duty of customs and therefore extended period of limitation cannot be invoked; that show cause notice is time barred and therefore, demanding interest and imposition of penalty is liable to be set aside; that the appellant were having sufficient balance of credit in the Cenvat credit account and credit was reversed even before show cause notice and therefore, demand of interest and imposition of penalty are not sustainable.
- 3.1 Impugned Order 2 : Aggrieved with the impugned order, the appellant preferred appeal, *inter alia*, contending in respect of the impugned order 1 that demand of Cenvat credit for the period June, 2007 to February, 2008 is time barred as they have were regularly filing periodical returns; that the Show Cause Notice alleges non-reversal of credit on 109.612 MT is Rs. 6,68,670/-; that show cause notice is time barred and therefore, demanding interest and imposition of penalty is liable to be set aside; that the appellant were having sufficient balance of credit in Cenvat credit account and credit was reversed even before show cause notice and therefore, demand of interest and imposition of penalty are not sustainable.
- 4. Personal hearing in the matter was attended to by Shri Vikas Mehta, Consultant who reiterated the grounds of appeals and submitted that they do not want to add any thing further. Personal hearing notice was sent to the Department, however, no one appeared.

į,



Findings:

- 5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned orders, grounds of appeals and oral and written submissions made by both the appellant. The issues to be decided in the present appeals are:-
 - (i) whether the impugned orders confirming demand of Cenvat credit on the imported goods cleared as such under Rule 14 of the Rules read with Section 11A(4) / proviso to Section 11A(1) of the Central Excise Act, 1944 along with interest, is proper or not; and
 - (ii) whether penalty equal to non reversed Cenvat credit is imposable under Rule 15 of Rules read with Section 11AC of the Act or not.
- I find that the appellant is not contesting confirmation of demands on merits 6. but contended that the demands are time barred as they were regularly filing statutory periodical returns and therefore, proceedings are required to be set aside. I find that simpliciter by filing periodical returns the appellant cannot shift buck to the Department contending that they have disclosed their acts. Filing periodical returns should not be considered panacea to every evils/ills or atonement for all sorts of acts. It was incumbent upon the appellant to have explained along with facts, figures, documents and justification as to how mere filing of the periodical returns, the department was made aware of exact details of clearances of goods 'as such' and its quantification of reversal of credit. The appellant had not submitted any details or documents in respect of goods cleared 'as such' to the Department and unless the officers verified the documents and co-related and cross-tallied credit amounts by going through the records in detail the violation could not have been detected by the CERA/Audit. Also, quite importantly, I find in case of the impugned order-1 the lower adjudicating authority has held at Para 19 the appellant agreeing to audit objection has voluntarily reversed Rs. 92,47,736/- against their liability of Additional Excise duty (SAD) without any protest. The lower adjudicating authority has also appropriated Cenvat credit of Rs. 92,47,736/- voluntarily paid by the appellant and therefore, the appellant cannot somersault and now again start contesting the amount reversed during audit of their own volition.
- 6.1 In case of the impugned order 2, they have not reversed Cenvat credit on 109.612 MT of the imported goods cleared as such. The appellant was required to reverse Cenvat credit of Rs. 61,27,354/- in respect of the confirmed demand which they have not paid or reversed. The appellant, in respect of the impugned order -2 has also raised contention of time bar of demand as they had filed periodical returns. Here, I would like to replicate findings in respect of the impugned order -1 and further add that the contention of time bar of demand is also not sustainable.

as even after pointing out of lacunae the appellant had not bothered to reverse the Cenvat credit as held by the lower adjudicating authority at Para 28.2 as "28.2 ……... I find that the act of noticee was not bonafide because the noticee had not reversed the Cenvat credit of Rs. 61,27,354/- even after the objection raised by the audit. Had it not been pointed out by the Audit, the fact of non-reversal of the Cenvat credit would have gone unnoticed. Thus, it proves that the intention of the noticee is malafide and hence, penalty becomes integral part. ……"

- During the course of personal hearing too, the appellant has not submitted any documents or any further submissions to support their claim or contentions on time bar or quantification of demand or any other pleas.
- 6.3 I find that the appellant has failed to reverse appropriate Cenvat credit on the imported goods cleared 'as such' for the extended period from June, 2007 to February, 2008 on multiple clearance transactions. Two demand notices have also been issued consequently leading to passing of the impugned orders confirming demands along with interest and imposition of penalty under Rule 15 of Rules read with Section 11AC of the Act. I therefore, find that imposition of penalty is legal and proper and is required to be upheld.
- 7. In view of above, I uphold the impugned orders and reject both the appeals.
- 7.1. अपीलकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई अपीलों का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
- 7.1 The appeals filed by the appellants are disposed off in above terms.

्रसन्यापितंः भिर्मितं निखिल ऐ. हपारेलिया अधीक्षक (अगील्क) (कुमार संतोष) आयुक्त (अपील्स)

By R.P.A.D.

To, M/s. GPT Steel Industries Ltd. Plot No. 301, GIDC, Phase-II, Mithirohar, Gandhidham (Kutch).

Copy for kind information and necessary action to:

- 1) The Chief Commissioner, CGST & CX, Ahmedabad Zone for his kind information.
- The Commissioner, CGST & CX, Gandhidham, Kutch Commissionerate.

 Guard File.